संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) चूंकि, प्रस्तावित डाकघर के लिये अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नियुक्ति की औपचारिकताओं को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका, इसलिए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का खोलना स्थगित करने के आदेश गए।

Sanction of telephones on the recommendations of MPs

407. SHRI MOHAMMED AFZAL ALIAS MEKM AFZAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that tele phono connections, in excess of the quota prescribed for *M.Vs.* have been .-anctioned on the recommendations of certain M.Ps. during the period from 1st April, 1992 to the 31st March, 1993;

(b) if so, what are the names of such M.Ps. of Lok Sabha and Rajya Sabha separately and the number of telephone connections sanctioned in the name of each of them;

(c) what is the number of telephone connections sanctioned for Delhi and outside Delhi on the recommendation of each M.P. during the above period;

(d) what are the reasons for sanc tioning telephone connections in ex cess of the prescrbed quota; and

(e) whether Government are pre pared to grant this concession to other M.Ps. also?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICA TIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) M.Ps. sometimes receive requ ests for in excess of their quota from ihwr constituencies. Some are sanctioned in exercise of discretionary powers based on an objective assessment of their needs of tha prospective subsecriber.

(e) Every case is considered on its merit.

Reforming of telecom sector in the country

408. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of COMMUNI-CATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to reform the telecom, sector in the country.

(b) whether it is also a fact ihat the Telecom, unions are resisting the reforming of telecom sector;

(c) if so, the manner in which telecom sector is proposed to be reformed stating the areas of opposing by the telecom unions; and

(d) whether any settlement has been arrived at in respect of the issues involved?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICA TIONS (SHRI SUKH RAM): (a) to (d) Proposals for restructuring of Department of Telecommunications and related issues including staff matters are under consideration of the Government-

Proposal to stop purchase etc. of telephone instruments

409. SHRI SURESH KALMADI: SHRI GOVINDRAO ADIK:

Will the Minister of COMMUNI-CATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Department of Telecommunications

propose to stop the purchase, installation and maintenance of telephone instruments, thus affecting millions of new telephone subscribers all over the country; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKM RAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of (a).

डाकघर खोलने के मानदंड

411. श्री अनन्त राय जायसवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय को ग्राम–त्रिमुहानी घाट जिला दरभंगा (बिहार) में डाकघर खोले जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने डाकघर खोलने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक खोले जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां । उक्त डाकघर नहीं खोला जा सकता, क्योंकि यह राजस्व ग्राम "जरिआओं" का एक पुरवा है और जरिआओं में एक डाकघर पहले से ही है।

(ख) जी हां । शाखा डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों की एक प्रतिलिपि विवरण (नीचे देखिए) में दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

शाखा डाकघर खोलने के लिये मानदंड व मार्गदर्शी सिद्धांत

(1) जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में:–

एक ग्राम–समूह (जिसमें वह गांव भी शामिल है, जहां डाकघर खोलने का प्रस्ताव है) की जनसंख्या 3000

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में :

किसी एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 या एक ग्राम समूह की जनसंख्या 1000.

(2) दूरी

(क) सामान्य क्षेत्रों में

मौजूदा नजदीकी डाकघर से दूरी कम से कम 3 कि.मी. होनी चाहिये।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में :

पहाड़ी इलाकों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी, जो ऊपर दी गई है । निदेशालय द्वारा उन मामलों में दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है, जहां विशेष परिस्थितियों के आधार पर ऐसी छूट अपेक्षित है । इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये।

(3) अनुमानित आय

(क) सामान्य क्षेत्रों में

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 33⅓ प्रतिशत होनी चाहिये।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होनी चाहिय।

Modernisation and Increasing the capa. cities of old and out dated exchanges

411. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of COMMUNICA-